Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

COE कनेक्ट

1 सितंबर 2025

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

प्रिय पाठकों,
हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है।
हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रिय पाठकों,
CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।
आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

जसवंत सिंह कालसी
मुख्य परिचालन अधिकारी

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

डीजीसीए से मंजूरी: कृषि ड्रोन 'अर्जुन' को मिली हरी झंडी

शहर स्थित ड्रोन निर्माता प्राइमा एयरोस्पेस को डीजीसीए से उसके कृषि ड्रोन 'अर्जुन' के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इस स्वीकृति के बाद कंपनी इसे फसल निगरानी और सटीक छिड़काव जैसे कृषि कार्यों में उपयोग कर सकेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रमाणपत्र कंपनी की संस्थापक और सीईओ धनश्री मंधानी को प्रदान किया। हाल ही में समूह की ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को आरपीटीओ (Remote Pilot Training Organisation) का दर्जा भी मिला है, जिससे ड्रोन निर्माण, प्रशिक्षण और तैनाती की संपूर्ण प्रक्रिया संभव हो पाई है।

इस वर्ष की शुरुआत में, प्राइम ग्रुप ने दावोस में राज्य सरकार के साथ 300 करोड़ रुपये का एमओयू हस्ताक्षरित किया था, जिसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। इस मंजूरी के साथ, कंपनी पूरे देश में ड्रोन आधारित सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। अर्जुन जैसे कृषि ड्रोन किसानों को बेहतर उत्पादन, रसायनों की बचत और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित कर टिकाऊ खेती की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे।

रंगारेड्डी में नैनो उर्वरकों के साथ ड्रोन छिड़काव पर जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विभाग, आईसीएआर-केवीके (रंगारेड्डी) और आईसीएआर-सीआरआईडीए, हैदराबाद द्वारा नेदुनुरु गाँव, कंडकुरु मंडल, रंगारेड्डी ज़िले में ड्रोन आधारित कृषि तकनीकों पर जागरूकता कार्यक्रम और फील्ड डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को ड्रोन छिड़काव के लाभों से अवगत कराना था।

विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रोन केवल छिड़काव का साधन नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी तकनीक है, जो समय पर इनपुट प्रबंधन, श्रम की कमी और किसान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम जैसी समस्याओं का समाधान करती है। ड्रोन से उर्वरक व कीटनाशक समान रूप से वितरित होते हैं, समय और संसाधन बचते हैं तथा पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ती है।

नैनो उर्वरकों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया। धान में वे पौधों को मजबूत बनाकर कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों की हानि रोकते हैं। मक्का में 25–30 दिन और फूल आने की अवस्था में छिड़काव से उत्पादन में सुधार होता है। कार्यक्रम में लगभग 30 किसानों ने भाग लिया और ड्रोन छिड़काव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी देखा। किसानों को सरकारी योजनाओं व प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी भी दी गई।

कृषि पुनर्जीवन हेतु केरल लाएगा लीज़ खेती को वैध बनाने वाला विधेयक

तिरुवनंतपुरम, 30 अगस्त: केरल सरकार राज्य में लीज़ खेती को वैध बनाने के लिए एक नया विधेयक लाने जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम राज्य में बड़ी मात्रा में परती पड़ी भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने और कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने में सहायक होगा।

यह कानून आंध्र प्रदेश के 2019 के "क्रॉप कल्टीवेटर राइट्स एक्ट" की तर्ज पर बनाया जाएगा। वर्तमान में केरल में बटाई या किराए पर खेती तो प्रचलित है, परंतु यह भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत वैध नहीं है। विधिक मान्यता मिलने पर किसानों को बैंक ऋण, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

राज्य में वर्तमान में एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि परती पड़ी है, जिनमें से लगभग आधी भूमि स्थायी रूप से अनुपयोगी है। अधिकारी मानते हैं कि यह कदम भूमि मालिकों और कृषकों दोनों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि भूमि का स्वामित्व यथावत रहेगा और खेती भी जारी रह सकेगी। यह पहल 2016 में नीति आयोग के मॉडल भूमि लीज़िंग अधिनियम के बाद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पैडी उत्पादन हेतु आधुनिक तकनीकों पर किसान प्रशिक्षण: आईसीएआर-केवीके निंबुदेरा

निंबुदेरा, 25 अगस्त: आईसीएआर-केवीके निंबुदेरा ने 21 से 23 अगस्त तक सामिति हॉल, रांगत में “धान की खेती के लिए आधुनिक कृषि तकनीकें” विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत ज्ञान और व्यावहारिक कौशल देकर द्वीपीय परिस्थितियों में धान उत्पादन बढ़ाना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन परनसाला पंचायत के प्रधान श्री बालमुरुगन ने किया और वैज्ञानिक व टिकाऊ तरीकों को अपनाने पर बल दिया। डॉ. वी. दामोदरन, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, ने संसाधन सीमाओं और जलवायु चुनौतियों से निपटने में आधुनिक पद्धतियों की अहमियत बताई।

विशेषज्ञों ने बीज चयन, नर्सरी तैयारी, रोपाई तकनीक, जैविक खाद के उपयोग और पोषण प्रबंधन पर विस्तृत सत्र लिए। श्री राकेश दावर (कृषि विज्ञान) ने पोषक तत्व कमी की पहचान और कॉनोवीडर के प्रयोग का प्रदर्शन किया। इंजीनियर मनोज कुमार ने धान में यंत्रीकरण की भूमिका समझाई, जबकि अन्य विशेषज्ञों ने मछली–धान संयुक्त खेती और प्रसंस्करण पर जानकारी दी।

कार्यक्रम में 31 किसान और महिला कृषकों ने भाग लेकर आधुनिक पद्धतियों से उत्पादन सुधार के उपाय सीखे।

भारत का बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर

भारत के बागवानी क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। वर्ष 2024–25 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) में कुल बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो 2013–14 के 280.70 मिलियन टन से कहीं अधिक है। इसमें 114.51 मिलियन टन फल, 219.67 मिलियन टन सब्ज़ियाँ और 33.54 मिलियन टन अन्य बागवानी फसलें शामिल हैं। 2014–15 से 2023–24 के बीच फल उत्पादन लगभग 30% और सब्ज़ी उत्पादन 22% बढ़ा है। उत्पादकता में भी सुधार हुआ है—फलों में 14.17 से 15.80 टन प्रति हेक्टेयर तथा सब्ज़ियों में 17.76 से 18.40 टन प्रति हेक्टेयर तक वृद्धि हुई है।

यह सफलता मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जैसी योजनाओं के निरंतर सहयोग से संभव हुई है, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री का विकास, क्षेत्र विस्तार, पुराने बागानों का पुनर्जीवन तथा संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया गया है। प्रमुख पहलों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, क्लस्टर-आधारित विकास, जैविक खेती, जल संसाधन प्रबंधन तथा उन्नत भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना शामिल हैं। इन प्रयासों ने स्थिरता को सुदृढ़ किया है, फसलों की गुणवत्ता बढ़ाई है और किसानों की बाज़ार तक पहुँच को सशक्त बनाया है, जिससे भारत का बागवानी क्षेत्र निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है।

हिमाचल में अगले सत्र से स्कूलों और कॉलेजों में बागवानी विषय

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों और कॉलेजों में बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। यह पहल कक्षा 9 से 12 तक के साथ-साथ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक लागू होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और उद्यमिता की समझ विकसित करना है। राज्य की अर्थव्यवस्था में बागवानी, विशेषकर सेब, आम, खट्टे फल और अन्य फसलों के माध्यम से, महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे में यह कदम छात्रों के लिए खेती, प्रसंस्करण, विपणन और संबद्ध उद्योगों में करियर के नए अवसर खोलेगा।

यह प्रयास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ-साथ सीधे रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर पर बागवानी को पढ़ाने से बच्चों में टिकाऊ कृषि, पर्यावरणीय संतुलन और राज्य की कृषि परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। ग्रामीण आबादी का लगभग 90% हिस्सा खेती से जुड़ा होने के कारण यह पहल युवाओं के लिए बागवानी को केवल आजीविका नहीं, बल्कि एक आधुनिक, लाभदायक और सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में स्थापित करेगी।

तिरुचि: पच्चमलाई पहाड़ियों में जनजातीय आजीविका सशक्त करने हेतु 'सीड विलेज योजना' शुरू

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR), बेंगलुरु ने तुरैयूर के पास पच्चमलाई पहाड़ियों में सीड विलेज योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की आजीविका को सशक्त करना है। इस मॉडल को पहली बार किसी पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत किसान केवल बीज उत्पादन के लिए सब्ज़ियों की खेती करेंगे, जिन्हें सीधे IIHR द्वारा खरीदा जाएगा। इससे किसानों को निश्चित आमदनी सुनिश्चित होगी और बिना बिके उत्पाद को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। यह पहल तमिलनाडु के आदिवासी कल्याण विभाग के सहयोग से क्षेत्र में टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा देने के प्रयासों का हिस्सा है।

अब तक 125 जनजातीय किसानों ने टमाटर, मिर्च, आम, अमरूद और पपीता जैसी फसलों की सफलतापूर्वक खेती की है, जबकि 400 परिवारों को रसोई बागवानी के लिए बीन्स के बीज किट वितरित किए गए हैं। पिछले वर्ष परीक्षण आधार पर शुरू की गई यह योजना अब व्यापक स्तर पर लागू की गई है। किसानों को जैविक खाद और आवश्यक बागवानी सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। यह पहल लगभग 250 किसानों को लाभान्वित करेगी और फल व सब्ज़ी उत्पादन के माध्यम से स्थायी आजीविका को मजबूत करेगी।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत बागवानी जागरूकता अभियान आयोजित

तवांग, अरुणाचल प्रदेश: डुइटोंगखर सर्कल में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (VVP) और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के अंतर्गत बागवानी जागरूकता सह इनपुट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, स्थानीय उपयुक्त फसलों का प्रोत्साहन करना और इनपुट किट वितरित कर उत्पादकता व ग्रामीण आय को बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में तरल खाद, जैव-कीटनाशक, फफूंदनाशी और दानेदार खाद जैसे जैविक इनपुट्स पर प्रदर्शन किया गया, जिससे इनके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों को समझाया गया। किसानों को समूह खेती अपनाने, बाज़ार तक बेहतर पहुंच बनाने और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार टिकाऊ खेती की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि 48 कृषक परिवारों को बागवानी इनपुट किट का वितरण रहा। प्रत्येक किट में 12 प्रकार के संकर सब्ज़ियों के बीज, जैविक खाद, पौध संरक्षण सामग्रियाँ और कृषि स्प्रेयर शामिल थे। इस आयोजन में स्थानीय प्रतिनिधियों, बागवानी अधिकारियों और सुरक्षा बलों की सक्रिय भागीदारी रही, जो सीमा क्षेत्रों में स्थित समुदायों को टिकाऊ बागवानी और पर्यावरण हितैषी ग्रामीण विकास के माध्यम से सशक्त बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पशुपालन विभाग करेगा ई-समृद्ध डिजिटल पशुधन एवं ई-हेल्थ प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ

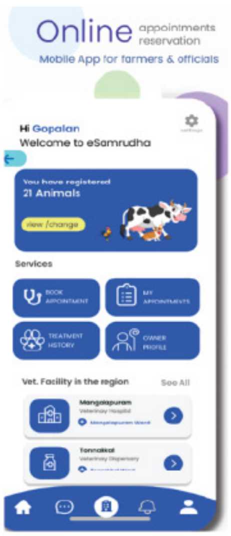

राज्य पशुपालन विभाग 30 अगस्त को अडूर में ई-समृद्धा नामक एक व्यापक डिजिटल पशुधन और ई-हेल्थ प्रबंधन प्रणाली लॉन्च करने जा रहा है। ₹7.5 करोड़ के निवेश के साथ यह पहल राज्यभर में पशुधन सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पथानामथिट्टा जिले में सफलतापूर्वक पायलट परीक्षण के बाद अब इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। ई-समृद्धा का उद्देश्य एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करना है, जिससे किसानों और पशु चिकित्सकों को बेहतर दक्षता और पहुंच सुनिश्चित हो सके। प्रमुख विशेषताओं में पशु स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन, ओपी परामर्श के लिए ऑनलाइन बुकिंग, किसानों और विभागीय अधिकारियों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, विभागीय प्रयोगशालाओं के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली और प्रजनन प्रबंधन सेवाएं शामिल हैं।

डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के सहयोग से विकसित यह प्रणाली 130 पशु चिकित्सा संस्थानों में लागू की जाएगी, जिनमें मल्टी-स्पेशियलिटी पशु अस्पताल भी शामिल हैं। विभाग को उम्मीद है कि यह डिजिटल पहल सेवा वितरण को बेहतर बनाएगी, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करेगी और पशुधन क्षेत्र के हितधारकों को संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगी।

भारत में पहली बार जारी हुई पशुओं के लिए रक्त संक्रमण और रक्त बैंक की राष्ट्रीय दिशानिर्देश

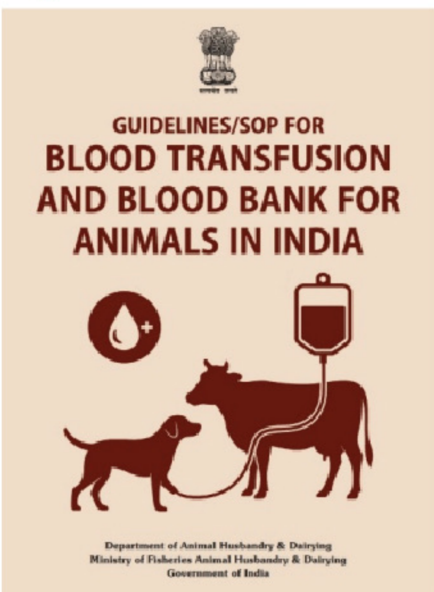

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने भारत में पहली बार पशुओं के लिए रक्त संक्रमण और रक्त बैंक की राष्ट्रीय दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) जारी की हैं, जिससे पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण कमी पूरी हुई है।

अब तक भारत में पशुओं के रक्त संक्रमण आपातकालीन स्थितियों में बिना किसी मानकीकृत स्क्रीनिंग या भंडारण प्रोटोकॉल के किए जाते थे। नया ढांचा दाता चयन, रक्त संग्रह, घटक प्रसंस्करण, भंडारण, संक्रमण प्रक्रियाएं, निगरानी और सुरक्षा उपायों को कवर करता है।

यह दिशानिर्देश भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ICAR संस्थानों, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और चिकित्सकों के इनपुट के साथ विकसित किए गए हैं। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं और ज़ूनोटिक जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए वन हेल्थ सिद्धांतों को शामिल करते हैं।

प्रमुख विशेषताओं में स्वैच्छिक और नैतिक रक्तदान, अनिवार्य रक्त टाइपिंग और क्रॉस-मैचिंग, दाता अधिकार चार्टर, डिजिटल रजिस्ट्रियां, रीयल-टाइम इन्वेंट्री और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की रिपोर्टिंग की व्यवस्था शामिल हैं। यह रोडमैप मोबाइल रक्त संग्रह इकाइयों, क्रायोप्रिजर्वेशन और दाता-प्राप्तकर्ता मिलान के लिए डिजिटल एप्लिकेशन के साथ एक राष्ट्रीय पशु चिकित्सा रक्त बैंक नेटवर्क की परिकल्पना करता है।

पंजाब का पशुपालन विभाग नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

पंजाब का पशुपालन विभाग पशुधन प्रबंधन और किसानों तक पहुंच के लिए अपने नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुआ है। पंजाब में आयोजित उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक (RRM) के दौरान विभाग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फेसबुक का प्रभावी उपयोग करने के लिए सराहा गया।

विभाग की डोरस्टेप कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को विशेष रूप से सराहा गया और अन्य उत्तरी राज्यों में इसे दोहराने की सिफारिश की गई। प्रमुख उपलब्धियों में 3.75 लाख सेक्स-सॉर्टेड सीमेन की खरीद, एफएमडी टीकाकरण लक्ष्य की 100% प्राप्ति, और FY 2024-25 में 22.26 लाख कृत्रिम गर्भाधान शामिल हैं। विभाग ने प्रजनन कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए 18.50 लाख सीमेन स्ट्रॉ भी तैयार किए।

बैठक में आठ उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, जहां पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पशुधन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई और 2025-26 के लिए प्राथमिकताओं की योजना बनाई गई।

पशु विश्वविद्यालय और PDFA का सहयोग: पंजाब में दुग्ध उत्पादन और आनुवंशिकी को मिलेगा बढ़ावा

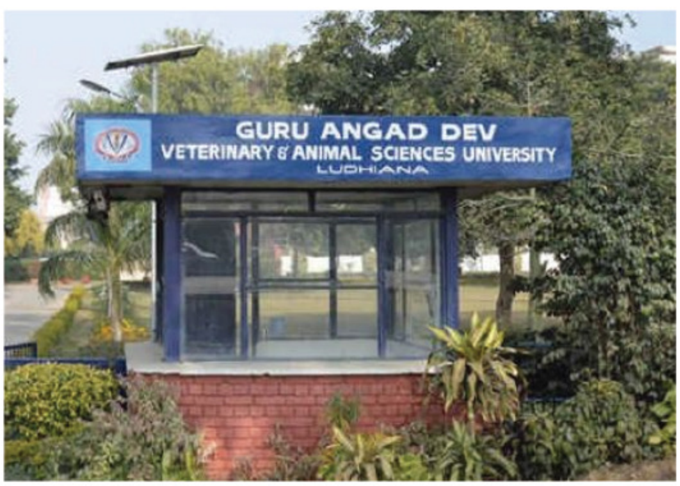

गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (GADVASU), लुधियाना ने प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन (PDFA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य पंजाब में पशु आनुवंशिकी को उन्नत करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है।

इस साझेदारी के तहत PDFA सदस्यों के झुंडों से चुने गए श्रेष्ठ होल्स्टीन फ्रिज़ियन (HF) और जर्सी नर बछड़ों की प्रजनन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। विश्वविद्यालय इन बछड़ों से उच्च गुणवत्ता वाला जमे हुए सीमेन तैयार करेगा और इसे PDFA के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराएगा।

इस पहल से श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी, सटीक डेटा के साथ संतति परीक्षण संभव होगा और सतत आनुवंशिक उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। GADVASU अधिकारियों ने बताया कि यह सहयोग दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएगा, किसानों की महंगे आयातित सीमेन पर निर्भरता कम करेगा और पशुधन सुधार का दीर्घकालिक मॉडल स्थापित करेगा। HF और जर्सी मवेशी पंजाब के झुंड का लगभग 80% हिस्सा हैं और राज्य के दुग्ध उत्पादन में 40% योगदान देते हैं। यह कार्यक्रम पंजाब को डेयरी आनुवंशिकी में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगा।

भारत और भूटान ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और भूटान ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 28 अगस्त 2025 को थिम्फू में भारत के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और भूटान के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय (MoAL) के सचिव थिनले नामग्येल द्वारा किया गया। यह समझौता कृषि अनुसंधान और नवाचार, पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला विकास तथा ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग का ढांचा प्रदान करता है। यह दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समझौते के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त तकनीकी कार्यदल (JTWG) की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया और तात्कालिक कार्यों हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। चर्चा में कृषि, पशुधन, बीज क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन, सहकारिता, अनुसंधान सहयोग और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दे शामिल रहे।

अगली JTWG बैठक भारत में आपसी सहमति से तय की गई तिथि पर आयोजित की जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच कृषि विकास और लचीलापन बढ़ाने में सहयोग और मजबूत होगा।

भारत और डब्ल्यूएफपी में खाद्य सुरक्षा सहयोग पर उच्चस्तरीय चर्चा

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के उप कार्यकारी निदेशक और सीओओ श्री कार्ल स्काउ ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी से कृषिभवन में भेंट की। बैठक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूएफपी की सहभागिता और साझेदारी पर चर्चा हुई।

डॉ. चतुर्वेदी ने भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी के रूप में स्थापित करने की प्रधानमंत्री की दृष्टि साझा की और दक्षिण–दक्षिण सहयोग को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया। उन्होंने डिजिटल कृषि, फसल बीमा, ट्रैसेबिलिटी और आईसीएआर द्वारा विकसित पोषक तत्व समृद्ध किस्मों जैसी पहलों पर प्रकाश डाला।

श्री स्काउ ने खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की और कहा कि भारत के अनुभव—जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, विविधीकरण, फोर्टिफिकेशन, महिलाओं का सशक्तिकरण और जलवायु अनुकूल आजीविकाएँ—अन्य देशों के लिए मूल्यवान उदाहरण हैं। उन्होंने वैश्विक खाद्य असुरक्षा से निपटने में भारत के साथ सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सीईएफएमआई (CEFMI) ने ईकेएल सीएसआर फाउंडेशन (EKL CSR Foundation) के साथ मिलकर हरियाणा में एफपीओ (FPO) नेतृत्व को मज़बूत किया

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइज़ेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI) ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (EKL) के सहयोग से तीन दिवसीय आवासीय क्षमता-विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह कार्यक्रम एस्कॉर्ट्स कुबोटा एडवांस्ड फार्मिंग इंस्टीट्यूट (EKFAI), कुरुक्षेत्र, हरियाणा में 25 से 27 अगस्त 2025 तक हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के 29 एफपीओ (FPOs) से 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य एफपीओ की संगठनात्मक संरचना और सुशासन को मज़बूत करना, प्रतिभागियों की खेती में मशीनीकरण से जुड़ी समझ बढ़ाना और एग्री-बिज़नेस गतिविधियों के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं की जानकारी देना था। इसमें विशेष रूप से नेतृत्व क्षमता विकसित करने, बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाने और किसानों को सीधा लाभ पहुँचाने वाले टिकाऊ मशीनीकरण समाधानों पर ज़ोर दिया गया।

इंटरैक्टिव सत्रों, केस स्टडीज़ और समूह चर्चाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम ने एफपीओ नेताओं को अनुभव साझा करने, संचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजने और सामूहिक विकास के अवसर तलाशने का मंच दिया। आवासीय प्रारूप ने प्रतिभागियों को गहन सीखने का वातावरण दिया और आपसी सहयोग व सीखने की भावना को मज़बूत किया।

सश्वत मिठास पहल के तहत अयोध्या में क्लाइमेट-स्मार्ट गन्ना खेती को सशक्त बनाना

सश्वत मिठास पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI) और UPL SAS लिमिटेड मिलकर अयोध्या में टिकाऊ गन्ना खेती की प्रथाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक 500 किसानों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 90 असंगठित किसान समूह और 3 संगठित किसान समूह शामिल हैं। इस सर्वेक्षण से मिली जानकारी के आधार पर गाँव-स्तर पर प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए गए हैं, जहाँ पानी के कुशल उपयोग, मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन और जैविक उर्वरकों के उपयोग जैसे अच्छे तरीकों को दिखाया जा रहा है।

किसानों की भागीदारी और आपसी सीख को बढ़ावा देने के लिए इस पहल के अंतर्गत 92 रिटेलर विज़िट, 8 फील्ड डे, 3 संगठित बैठकें और 90 असंगठित बैठकें आयोजित की गई हैं। इन माध्यमों से किसानों को विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करने, अपनी समस्याएँ साझा करने और जलवायु-प्रतिरोधी खेती की तकनीकों को देखने-समझने का अवसर मिला है।

मैदानी शोध, व्यावहारिक प्रदर्शन और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यह पहल किसानों को ऐसे पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-कुशल तरीके अपनाने में मदद कर रही है, जिनसे उत्पादन बढ़े, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकसित हो। इसका बड़ा उद्देश्य सिर्फ गन्ना उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि अयोध्या क्षेत्र में एक ऐसा मॉडल तैयार करना भी है जो टिकाऊ कृषि और समावेशी विकास का उदाहरण बने।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india